of the Distribution Companies on various issues, with a view to providing better quality service to the consumers.

SHRI K. RAHMAN KHAN: Mr. Chairman, sir, the answer is not related to the question which I have asked. I want to know, after the privatisation of distribution of power in Delhi, whether the Government has made any assessment of the difficulties experienced by the consumers in getting connections. One year is over. What is the assessment of the Delhi Government, as far as privatisation is concerned? I would to know whether new connections are being given. That reply is not there. I would be grateful to the hon. Minister, if he informs the House.

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति जी, बिजली का वितरण पूर्णत: राज्यों का विषय है। दिल्ली प्रदेश की सरकार ने वितरण का निजीकरण किया है। जितनी भी शिकायतें आती है, इन शिकायतों को कम करने के लिए सभी राज्यों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन किया है। इन राज्य विद्युत नियामक आयोगों को पूरे अधिकार दिए गए हैं। दिल्ली में निजीकरण के बाद दिल्ली राज्य विद्युत नियामक आयोग से मुझे जानकारी मिली है, उसके अध्यक्ष से मेरी बात हुई और मुझे उन्होंने जानकारी दी है कि पिछले वर्ष की तुलना में दिल्ली में बिजली वितरण में कुछ सुधार आया है। इस प्रकार की उनकी राय है।

SHRI K. RAHMAN KHAN: My second supplementary is: What are the number of requests for granting connections pending with different zones and the dates of such requests? This information should be furnished.

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति जी, यह राज्यों का विषय होने के नाते मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मैं राज्य सरकार से जानकारी मंगवा कर माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा।

MoU signed betwen PGCI and State Grid Corporation of China

*246. DR. T. SUBBARAMI REDDY:
SHRI K. NATWAR SINGH:†

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the Power Grid Corporation of India limited has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with State Grid Corporation of China on 9th July, 2003;

---

*The question was actually asked on the floor of the House by Shri K. Natwar Singh.

(b) if so, to what extent this will help in developing the power generation and power distribution in India; and

(c) by when the work on this MoU is likely to be started?

THE MINISTER OF POWER (SHRI ANANT GANGARAM GEETE): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) The Memorandum of Understanding does not cover power generation or distribution area. The Memorandum of Understanding envisages sharing of experience in the field of transmission system and telecommunication.

(c) The Memorandum of Understanding has become effective from the date of its signing, i.e. 9.7.2003 and will remain in force for a period of three years.

SHRI K. NATWAR SINGH: Sir, I have no questions. I am satisfied with his statement.

श्री आर. पी. गोयनका: सभापति महोदय, नटवर सिंह जी ने सवाल नहीं किया है इसलिए मुझे कुछ कमजोरी महसूस हो रही है। फिर भी, मैं एक सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। इन्होंने चाइना से डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में एग्रीमेंट किया है, यह बहुत अच्छी बात है। जो जानकारी आपको वहां से मिली, इसको सारे देश में और लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रेड में हैं, उनको दे दी जाये तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति महोदय, जो पावर ग्रिड का एमओयू चाइना के साथ साइन हुआ है, वह ट्रांसमिशन के क्षेत्र में हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन और जेनरेशन के क्षेत्र में नहीं हुआ है। जो एमओयू साइन हुआ है, उससे जितना भी हमारा अथवा उनका अनुभव है, हमने अपने उन अनुभवों को शेयर करने के लिए एमओयू बनाया है और निश्चित रूप से इसका लाभ देश के सभी राज्यों को मिल सकता है।

श्री मोती लाल वोरा: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो Memorandum of Understanding आपने साइन किया है, उसमें आपने कहा है कि हम इससे ट्रांसमिशन और टेलीकम्यूनीकेशन के क्षेत्र में उनके अनुभव का लाभ लेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतवर्ष में अनुभव की इतनी कमी है कि हमें इसके लिए एमओयू साइन करना पड़ा। भारतवर्ष में हर जगह इतना उत्पादन हो रहा है, फिर चाइना के साथ

केवल इसलिए एमओयू साइन करना कि हमें टैलीकम्यूनीकेशन के क्षेत्र में ऐक्सपीरिएंस हो जाए, क्या भारतवर्ष में अनुभव की इतनी अधिक कमी है?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: महोदय, भारतवर्ष में अनुभव की कोई कमी नहीं है।

श्री मोती लाल वोरा: फिर ऐसा क्यों है? सभापति महोदय, अगर कमी नहीं है तो फिर इस Memorandum of Understanding को साइन करने की आवश्यकता क्या थी? What is the necessity of signing the MoU now?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: महोदय, भारतवर्ष में अनुभव की कोई कमी नहीं है बल्कि ट्रांसमिशन के क्षेत्र में हम कुछ हद तक चाइना से आगे हैं। यह जो एमओयू साइन हुआ है, इससे हम केवल उनसे लेंगे नहीं, बल्कि उन्हें देने के लिए भी यह ऐग्रीमेंट किया गया है।

Funds for poverty alleviation in KBK districts of Orissa

*247. SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the amount given to the eight KBK districts in Orissa for poverty alleviation programmes from 1995 to 2003, year-wise and district-wise;

(b) whether Government have approved any agency other than State Government to review this poverty alleviation programme in all KBK districts;

(c) whether it is a fact that the funds which were given for poverty alleviation programme could not be fully utilized; and

(d) if so, the details of funds utilized from 1995–2003?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI ANNASAHEB M.K. PATIL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Year-wise and district-wise Central funds released by the Ministry of Rural Development under poverty alleviation programmes to KBK districts of Orissa during 1995-96 to 2002-2003 are given in Statement-I. (*See* below)

2. No other agency has been approved by the Ministry to review the poverty alleviation programme in KBK district of Orissa.

3. The details of funds utilized under poverty alleviation programmes in the KBK districts of Orissa are given at Statement-II.